POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को बहु उद्देश्यपूर्ण बनाने के मकसद से राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को आधुनिक कॉमन सर्विस सेंटर में बदला जा रहा है।

इससे गांव के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए तहसीलों और जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और डिजिटल जैसी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल सकेंगी।

ढाई हजार करोड़ की लागत से पहले से खुले पैक्स का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। साथ ही देश की हर ग्राम पंचायतों में पैक्स सुविधा के लिए 2029 तक दो लाख नए पैक्स खोलने का लक्ष्य है। इससे 17 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।

गांवों में पैक्स अब केवल ऋण केंद्र ही नहीं बल्कि आधार, नामांकन, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, रेल-बस टिकट, दवाइयां, पेट्रोल-डीजल जैसी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल और वित्तीय सशक्तिकरण की नींव रखेगा।

गांव का किसान हो या मजदूर अपने गांव में ही बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेगा। राजस्थान में भूमि विकास बैंकों को 860 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है, जिससे इन्हें घाटे से बाहर लाकर लाभ में बदला जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह खुद देश के हर गांव तक पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने की मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। सही रणनीति और तकनीकी उन्नयन के साथ सहकारी संस्थाएं आने वाले वर्षों में गांवों को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

आदिवासी महिला भी संपत्ति में बराबर की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आदिवासी समुदाय की महिलाएं और उनके कानूनी वारिस भी पुश्तैनी संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। कोर्ट ने इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति से वंचित करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन भी करता है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। कोर्ट ने पुरुष वारिसों को ही संपत्ति देने को गलत बताया और कहा कि महिलाओं को संपत्ति से वंचित करना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में जब समानता की दिशा में कई कदम उठाए जा चुके हैं, तब भी महिलाओं को संपत्ति से वंचित रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरतलब है कि यह फैसला दहिया नाम की महिला की याचिका पर दिया गया है, जिसे निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था।

परीक्षार्थी महिला को बस में सीट नहीं दी, रोडवेज पर लगाया हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में ममता कुमारी सैनी ने रोडवेज, जयपुर आगार के मुख्य प्रबंधक व रोडवेज चेयरमैन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उनके अधिवक्ता ने बताया कि

स्कूल लेक्चरार भर्ती-2018 की 3 जनवरी 2020 को होने वाली परीक्षा में परिवादिया को बीकानेर में सेंटर आवंटित था। परीक्षा के एक दिन पहले उसने बीकानेर जाने के लिए रोडवेज में खुद व अपने पति का ऑनलाइन टिकट लिया। उन्हें सीट नं. 45 व 46 आवंटित की गई। उनकी बस सुबह 11.40 बजे थी। वह पति के साथ 11 बजे सिंधीकैंप बस स्टैंड पहुंच कर बस में चढ़ी तो पता चला उसमें 40 सीट ही है। टिकट विंडो पर इंचार्ज ने उन्हें मौजूदा व अगली बस में सीट देने से मना कर उसे टिकट कैंसिल कराने को कहा। उन्हें वैकल्पिक बस भी उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरी में उन्होंने तत्काल रेल सेवा में टिकट लिया और ट्रेन से देर रात बीकानेर पहुंचे। इसमें उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ी।

उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई पर दोनों पक्षों को सुनकर रोडवेज प्रबंधन का गंभीर सेवादोष माना। आयोग ने रोडवेज प्रबंधन पर 61 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही परिवादीगण को ऑनलाइन टिकट की राशि 574 रुपए भी वापस देने का निर्देश दिया है।

'गिव अप' अभियान का असर...

'ग्राम गदर' कई बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपात्र लोगों द्वारा गैर वाजिब फायदा उठाने पर प्रश्नचिह्न लगाकर चिंता जाहिर करता रहा है। खुशी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे 'गिव अप' अभियान का असर अच्छे नतीजों के रूप में सामने आ रहा है।

स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रदेश के 25 लाख से भी अधिक लोगों ने खुद आगे बढ़कर खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान 27.62 लाख लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, जिससे उनके नाम स्वत: ही हट गए हैं। इसके चलते अब तक 54 लाख से ज्यादा नए पात्र वंचितों को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है।

अपात्र छोड़े सामाजिक पेंशन ...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने अपात्र लोगों को अपील जारी करते हुए कहा है कि सरकार पेंशन त्याग (गिव अप) को लेकर अभियान चलाने जा रही है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन में न्यूनतम आय का पैमाना है। वर्तमान में कई लाभार्थी इस पैमाने को पार कर चुके हैं। उनकी पेंशन अब नियमों के खिलाफ है। सरकार की अपील पर पेंशन त्याग नहीं किया तो भविष्य में ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ ब्याज सहित पेंशन वसूली की कार्रवाई की जाएगी। पात्र लोगों को ही समय पर इस योजना का लाभ मिल सके, इस वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है, वृद्धावस्था और एकल नारी के मामले में पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपए है, जबकि विशेष योग्यजन श्रेणी में वार्षिक आय सीमा 60 हजार रुपए तय है।

समय पर मिले फसल बीमा क्लेम

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि अब यदि बीमा कंपनियां किसानों को समय पर फसल बीमा क्लेम नहीं देंगी तो उन्हें किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज राशि किसान के खाते में सीधे डाली जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि बीमा कंपनी निर्धारित तिथि के 121 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उस पर यह ब्याज लगेगा। अब राज्य सरकारें भी अगर अपने हिस्से का भुगतान देर से करती है, तब भी किसानों को नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी समय पर जारी करेगी और राज्य की देरी पर भी 12 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार से लेकर किसान को दिया जाएगा।

औद्योगिक हब की तरफ बढ़ रहा प्रदेश

राजस्थान में निवेशकों और उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत 2300 निवेशकों को 765.78 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी कर दी

गई है। उद्योग विभाग का दावा है कि यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 293 प्रतिशत ज्यादा है।

इस भुगतान से जहां मौजूदा प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी, वहीं कतार में खड़े नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ने की उम्मीद है। उद्योगपतियों के अनुसार समय पर राशि नहीं मिलने से मशीनरी खरीद, उत्पादन विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन में दिक्कत आती रही है। बकाया इंसेंटिव और सब्सिडी समय पर मिलती रहे तो राजस्थान में इकोनॉमी का बूस्टअप और तेजी से होगा।

अपात्रों ने उठाई गरीबों की पेंशन

सरकारी ऑडिट में राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्यभर में 3.12 लाख अपात्र लोग गरीबों के हक की पेंशन उठाकर खा गए। इससे सरकारी खजाने को 318 करोड़ रुपए की चपत लगी है।

इन 3.12 लाख अपात्रों में लोग या तो मृत थे या पुनर्विवाह कर चुके थे। यह आंकड़ा इस सच्चाई को उजागर करता है कि जमीनी स्तर पर पात्रता की निगरानी लगभग निष्क्रिय पड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला सिस्टम की निष्क्रियता से ही संभव हुआ है। यदि समय पर मृत्यु रजिस्ट्रेशन, पुनर्विवाह सूचना और ई-केवाईसी को पेंशन सिस्टम से जोड़ा जाता, तो यह अनियमितता रोकी जा सकती थी। अब चुनौती यह है कि रकम कैसे व किस हद तक वसूली जा सकेगी।

मेक इन इंडिया को दें बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि वे संकल्प लें कि हमारे घर में जो कुछ भी

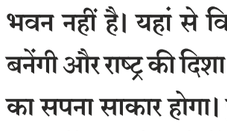

नया सामान आएगा, वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना है।

उन्होंने ट्रम्प टैरिफ वॉर के बीच अमरीका को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम उन वस्तुओं को खरीदेंगे, जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, तो सामने आता है कि दुनिया के सभी देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा।

साकार होगा विकसित भारत का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवालय के पहले भवन 'कर्तव्य भवन-3' का उद्घाटन किया। यह कॉमन सेंट्रल सेक्रेटिएट (सीसीएस) के 10 नये भवनों में से एक है। इसका उद्देश्य सभी मंत्रालय और विभागों को एक छत के नीचे लाना है।

प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि ये सिर्फ नये भवन नहीं है। यहां से विकसित भारत की नीतियां बनेंगी और राष्ट्र की दिशा तय होगी। विकसित भारत का सपना साकार होगा। पुराने भवनों में काम करते हुए हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। नए भवनों में ज्यादा दक्षता से काम कर देश को गरीबी मुक्त करना है। कर्तव्य भवन-3 में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम मंत्रालय व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा।

हर तहसील में हो पिपलांत्री जैसा गांव

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजसमंद स्थित पर्यावरण संरक्षण के मॉडल ग्राम पिपलांत्री में आयोजित पर्यावरण महोत्सव-2025 में कहा कि पर्यावरणविद् श्याम सुंदर पालीवाल के प्रयासों से यहां चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह 19 वर्षों में यहां के ग्रामीणों के पर्यावरण के प्रति प्रेम,आत्मीयता, समर्पण का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि यहां ग्रामीणों ने न केवल पौधे लगाए बल्कि उन्हें जीवित भी रखा। हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाना अपने आप में अनुपम उदाहरण है। प्रदेश की हर तहसील में पिपलांत्री जैसा गांव होना चाहिए। श्याम सुंदर पालीवाल (पद्मश्री) ने बताया कि पिपलांत्री में आज तक 14 से 15 लाख तक पौधे लगाए हैं, जिनमें एक लाख चंदन के वृक्ष शामिल है।

शुरू होगी धन-धान्य कृषि योजना

देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना अक्टूबर से शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। योजना में 6 वर्ष तक सालाना 24 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाएगी। भंडारण और सिंचाई सुविधाएं सुधरेंगी। किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा और स्थानीय स्तर पर कमाई के रास्ते बनाए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनेंगी। प्रत्येक धन-धान्य जिले में योजना की निगरानी हर महीने होगी। निगरानी 117 प्रमुख इंडिकेटर्स के जरिए की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा करेगा।

प्रदेश में बन रहे हैं अमृत सरोवर

देश में ग्रामीण विकास को मजबूती देने और जल की हर बूंद को सहेजने के लिए मिशन अमृत सरोवर योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस मिशन के तहत देशभर में अक्टूबर 2024 तक 68 हजार से अधिक जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16,630 अमृत सरोवर बने हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 5,839, कर्नाटक में 4,056 और राजस्थान में 3,138 सरोवर तैयार किए गए हैं। इस मिशन से जल संकट को कम करने में मदद मिली है। साथ ही सतही व भूजल की उपलब्धता बढ़ी है। प्रदेश में योजना को जन सहयोग से भी लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गांवों तक पहुंचेगी स्वास्थ जांच

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न रोगों की जांच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 42 मदर लैब, 135 हब लैब एवं 1,335 स्पॉक्स चिन्हित किए गए हैं। हब व स्पॉक मॉडल से गांव-कस्बों तक जांचों का दायरा बढ़ेगा।

नि:शुल्क जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से हब व स्पॉक मॉडल अपनाने की पहल की गई है। यह मॉडल अपनाने से जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा। मदर लैब व हब लैब में प्रमाणित उच्च गुणवत्ता के उपकरण स्थापित किए जाएंगे। सैम्पल कलेक्शन से लेकर क्वालिटी चैक तथा रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड लेबोरेट्री सूचना प्रबंधन के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

कौशलयुक्त युवा बनाएंगे पहचान

राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से इस वर्ष 663 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से लगभग 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें 683 करोड़ रुपए से भी अधिक का भत्ता वितरित किया है।

विश्व युवा कौशल दिवस पर केबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान की कामकाजी आबादी अब कुल जनसंख्या का 63 प्रतिशत हो चुकी है। यह 15 से 59 वर्ष की आयु-वर्ग की वह शक्ति है, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को सबसे युवा प्रदेश बना देगी।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485